(ग) यदि नहीं, तो इन झुग्गियों को हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सिविया उद्यान मार्ग पर मदर डेरी बूथ के समीप कुछ अनधिकृत झुग्गियां विद्यमान हैं । ये झुग्गियां पी एंड टी पाकेट में हैं । तथापि दूध के बूथ के आस पास मंदिर मार्ग की ओर इस जंक्शन पर हाल ही में कोई झुग्गियां नहीं बनी हैं ।

(ख) और (ग) ये झुग्गियां पुरानी हैं तथा यह पता लगाना बहुत कठिन है कि अनधिकृत झुग्गियां किसकी सहमति से बनी हैं। तथापि, सरकार इन अनधिकृत झुग्गी निवासियों को बेदखल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है । इस प्रयोजनार्थ, अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिये गये हैं ।

अखिल भारतीय मेयर परिषद् का सम्मेलन

2340. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय मेयर परिषद् के 23वें वार्षिक सम्मेलन में व्यक्त किये गये इस आशय के विचारों की जानकारी है कि देश के बड़े बड़े नगरों की उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शहरी समस्याओं के समाधान हेतु कई आयोगों का गठन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस किस आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और उनमें से कौन कौन सी सिफारिश लागू की गयी हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (घ) अक्तूबर, 1986 में हुई स्थानीय शासन और शहरी विकास के लिये केन्द्रीय परिषद् की 23वीं बैठक और केन्द्रीय परिषद तथा अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की 12वीं संयुक्त बैठक में नोट किया कि शहरों में तीव्रता से बढ़ रही शहरी मलिन बस्तियों की जटिल समस्या सहित शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित व्यापक सिफारिशें देने हेतु भारत सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग नियुक्त किया था । पालिका निकायों को प्रशासनिक रूप से लाभप्रद और वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाने की समिति ने अनेक सिफारिशें भी की हैं । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और वह उनके कार्यान्वियन के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर रहा है ।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी प्रथम अंतरिम रिपोर्ट जनवरी, 1987 में दे दी है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है । इस विषय पर सरकार द्वारा कोई अन्य आयोग गठित नहीं किया गया है ।

गारलैण्ड केनाल योजना

2341. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नदियों के अतिरिक्त पानी को सूखे क्षेत्रों में ले जाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रमुख कौन-कौन सी हैं और क्या इनमें से एक ऐसी योजना "गारलैण्ड केनाल योजना" थी ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को सब से पहले कब तैयार किया गया था ; और

(घ) इस योजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) नदियों को सम्बद्ध करके कम जल वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल अन्तरण करने के लिए सरकार द्वारा जल संसाधन विकास हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है तथा इसके प्रायद्वीपीय घटक के सम्बन्ध में अध्ययन शुरु किए गए हैं । गारलैंड नहर स्कीम पर विचार किया गया था तथा उसके तकनीकी रूप से अयुक्तियुक्त और आर्थिक रूप से प्रतिषेधक पाया गया था तथा उस पर आगे कार्रवाई नहीं की गई थी ।

Shortage of water in Delhi

2342. SHRI DINKARRAO GOVINDRAO PATIL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to meet the shortage of water in Delhi during the coming summer season; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Delhi Water Supply and Sewerage Disposal Undertaking is at present supplying about 404 mgd of water as against the supply of 337 mgd of water in the corresponding period of last year. The total water supply would go upto 412 MGD shortly. Water has been released in additional 41 unauthorised/regularised colonies since last summer. Water supply has also been extended in the various pockets developed by DDA and Group Housing Societies viz; Chaukhandi, Madipur, G-17 area, colonies of Uttam Nagar and new pockets of Bodela.

Water Supply to Mehrauli Township has been augmented as well as to Kanjawala Block by setting up new booster pumping station at Karela Majra. 16 new tubewells have been commissioned since last summer in various pockets in rural area to augment the existing supply. Investigations for taking additional trial bores in rural area are in progress.

Failure of operation flood programme

2343. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the corrective measures taken by Government for effective implementation of the Operation Flood Programme in the light of the recent evaluation report of the European Economic Communities?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): A joint mission of Consultants appointed by the European Economic Community (EEC) and the World Bank had visited India in July-August, 1986, to review Operation Flood II Project and to make an appraisal of the new project Operation Flood-III. The EEC have informed that the purpose of the study by the Consultants was not an overall evaluation of Operation Flood but to analyse specific aspects of the Project where knowledge had been considered insufficient for the preparation of a new project.

Since the draft reports indicated that the views of the Consultants did not necessarily represent any official view of the financing institution, the Government did not consider it appropriate to take any action in the matter.

Housing scheme for landless rural labour

2344. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the amount allocated and actually spent on the implementation of the scheme of housing for landless rural labour during the Seventh Five Year Plan;

(b) whether this scheme is also being implemented in U.P.; and

(c) if so, what are the details thereof and the amount allocated for the scheme in U. P.?